ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद (Australia-India Education and Skills Council) की दूसरी मीटिंग

संयुक्त विज्ञप्ति

निम्न पक्षों के बीच -

ऑस्ट्रेलिया सरकार का शिक्षा विभाग (Department of Education) एवं रोजगार एवं कार्यस्थल संबंध विभाग (Department of Employment and Workplace Relations)

और

भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) एवं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

24 अक्टूबर 2024

सिडनी, ऑस्ट्रेलिया

1. ऑस्ट्रेलिया सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय जेसन क्लेयर (Jason Clare) और कौशल एवं प्रशिक्षण मंत्री माननीय एंड्रयू गाइल्स (Andrew Giles) एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने 24 अक्टूबर 2024 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में **ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद** (AIESC) की दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता की।

2. ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य शिक्षा, कौशल एवं शोध के लिए मंत्रियों ने प्राथमिक द्विपक्षीय वार्तालाप के रूप में AIESEC के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

3. मंत्रियों ने शिक्षा एवं कौशल विकास को ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला के रूप में जाना और यह माना कि इनसे हमारे लोगों, संस्थाओं और राष्ट्रों के मध्य स्थायी संबंधों को बढ़ावा मिलता है। मंत्रियों ने हमारे दोनों देशों के मध्य **व्यापक रणनीतिक साझेदारी** (**Comprehensive Strategic Partnership**) के तहत शिक्षा, कौशल एवं शोध सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने के निर्णय की सराहना की।

4. मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया और भारत की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एवं कौशल की महत्ता पर चर्चा की। मंत्रियों ने **भविष्य के लिए साझेदारी** को अभिस्वीकृति प्रदान की: **भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा रणनीति** को भारत के गांधीनगर क्षेत्र में AIESC की उद्घाटन मीटिंग के दौरान प्रकाशित किया गया था और इसका लक्ष्य शिक्षा एवं शोध साझेदारी के द्वारा पारस्परिक लाभ को बढ़ाना है।

5. मंत्रियों ने शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने वाली एवं भारत और ऑस्ट्रेलिया के शैक्षणिक संस्थानों को मिलकर काम करने के अवसर प्रदान करने वाली भारत की **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** पर चर्चा की।

6. इस रणनीतिक संदर्भ पर ध्यान देते हुए, मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भविष्य कार्यबल का निर्माण करते हुए **आर्थिक विकास के मुख्य स्रोत के रूप में शिक्षा एवं कौशल** की भूमिका को देखते हुए, AIESC की चर्चाओं में इसे मुख्य रूप से शामिल किया जायेगा। इसमें नवीनीकरण को बढ़ावा देने और ज्ञान के निर्माता के रूप में शोध कार्यबल शामिल है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि शिक्षा और कौशल हमारे लोगों और राष्ट्रों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग में स्कूल, कौशल और उच्च शिक्षा, इन तीन क्षेत्रों में रणनीतिक वचनबद्धता शामिल की जानी चाहिए।

7. मंत्रियों ने AIESC की पिछली मीटिंग के बाद की प्रगति को जांचा और संस्थागत साझेदारियों सहित ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य शिक्षा, कौशल एवं शोध में सहयोग को निरंतर बढ़ावा देने पर भी विचार किया।

कार्यबल के लिए भविष्य की शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पूर्वानुमान

8. मंत्रियों ने वर्तमान और भविष्य के कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्रों को शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी के पारस्परिक अवसर पर चर्चा की। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, मंत्रियों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया में कार्यबल की आवश्यकताओं के लिए शिक्षा और कौशल साझेदारी को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें दोनों देशों द्वारा सहमति प्राप्त प्राथमिकता क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों और मानकों द्वारा समाधान प्रदान करना भी शामिल है।

9. मंत्रियों ने महत्वपूर्ण कौशल की कमी को पहचानने पर ज़ोर दिया और **जॉब्स एंड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया (Jobs and Skills Australia)** की **नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (National Council for Vocational Education and Training)** (NCVET) के साथ अगली साझेदारी को सराहा, जो भविष्य की शिक्षा एवं कौशल साझेदारी की जानकारी के लिए श्रम बाजार और योग्यता आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने का उद्देश्य रखती है।

10. मंत्रियों ने यह भी स्वीकार किया कि विशेष रूप से 21वीं सदी के भविष्य के कौशल, हरित कौशल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स और रोबोटिक्स में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुशल कार्यबल महत्वपूर्ण है। मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इन क्षेत्रों में **कुशल कार्यबल को बढ़ाने** के लिए नौकरी की भूमिकाओं को निर्धारित करने और योग्यताओं को विकसित करने के तरीकों के बारे में जानकारी साझा करने से दोनों देशों को लाभ मिलने की संभावना है।

11. मंत्रियों ने कृषि क्षेत्र में शिक्षा एवं कौशल सहयोग में प्रगति पर चर्चा की, जिसे **भारत में महत्वपूर्ण कौशल पाठ्यक्रम** (स्किल्स कोर्स) **विकसित करने** की हाल ही की परियोजना के तहत जांचा गया जिसमें भारतीय कृषि श्रमिकों को उभरती टेक्नोलॉजी वाली नौकरी की भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया था। परियोजना में कृषि क्षेत्र के लिए 5 नए योग्यता पैकेज और 20 राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक शामिल किए गए। मंत्रियों ने अधिकारियों से भारत में इन पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के तरीकों की पहचान करने के लिए कहा। मंत्रियों ने इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने पर सहमति दी और भारत और ऑस्ट्रेलिया में छत पर सौर ऊर्जा क्षेत्र के उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण कौशल पाठ्यक्रमों को बनाने और विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई।

12. मंत्रियों ने दिसंबर 2024 में **प्रतिभाशाली प्रारंभिक-पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना** (MATES) के आगामी कार्यान्वयन और हाल ही के स्नातकों (ग्रैजुएट्स) और शुरुआती करियर पेशेवरों द्वारा कार्यक्रम की संभावित उच्च मांग पर चर्चा की। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच निर्धारित क्षेत्रों में लाभकारी कौशल एवं ज्ञान को साझा करने का भविष्य रोमांचक है।

13. मंत्रियों ने स्नातकों के लिए रोजगार क्षमता में सुधार के महत्व पर सहमति व्यक्त की। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए, मंत्रियों ने 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए संस्थानों को उद्योग के साथ साझेदारी करने की सलाह दी। मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी, कार्य-एकीकृत शिक्षा और प्रैक्टिकल प्लेसमेंट सहित इंटर्नशिप अवसरों के मॉडल पर सलाह प्रदान करने के लिए **ऑस्ट्रेलिया-भारत CEO फोरम** की महत्वपूर्ण भूमिका है। फोरम के शिक्षा संयुक्त कार्य समूह द्वारा ऑस्ट्रेलिया और भारत में व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए पाँच क्षेत्रों की पहचान की गई है - (क) पाठ्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीयकरण और इसकी अनुकूलता (ख) ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच विश्वीय रोजगार के लिए उद्योग-शिक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना (ग) ऑस्ट्रेलिया और भारत के लिए आर्थिक परिणाम प्राप्त करने के लिए उद्योग के साथ शोध साझेदारी को सशक्त बनाना (घ) पारस्परिक मान्यता (ङ) छात्रों और शोधकर्ताओं की दो-तरफ़ा गतिशीलता।

14. दोनों मंत्रियों ने भविष्य के कार्यबल को विकसित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने शिक्षकों को तैयार करने और पाठ्यक्रम को विकसित करने में साझेदारी निभाने पर सहमति व्यक्त की जिसे भारतीय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कौशल विषय पाठ्यक्रम एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल में आस्ट्रेलियाई सर्टिफिकेट III की तुलना करते हुए किया जायेगा। इससे आगामी अध्ययन

के लिए रास्ता खुलेगा और भारत में **प्रारंभिक शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों** के कार्यबल का विकास होगा।

15. मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं को समझने, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति के लिए नवीन दृष्टिकोण उपयोग करने और सहायक एवं समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए शिक्षण मानकों में सहयोग प्रदान किया जायेगा। इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए **शिक्षकों के लिए आस्ट्रेलियाई व्यावसायिक मानकों** और भारत के **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों** को ध्यान में रखा जाएगा।

कौशल अंतर को शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से मिटाना

16. मंत्रियों ने भारत की **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** द्वारा भारत में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों और VET संस्थानों के लिए और कुशल कार्यबल के विकास सहित पारस्परिक लाभकारी साझेदारी के लिए नए उत्पन्न अवसरों पर चर्चा की।

17. मंत्रियों ने भारत में ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज द्वारा कैंपस और साझेदारी स्थापित करने के निरंतर प्रयासों को सराहा और **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी** (GIFT सिटी) में डीकिन यूनिवर्सिटी और वॉलोन्गॉन्ग यूनिवर्सिटी के सफल उद्घाटन के बारे में चर्चा की। मंत्रियों ने अधिक से अधिक ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्रियों ने इनोवेटिव रिसर्च यूनिवर्सिटीज (IRU) के भारतीय यूनिवर्सिटीज के साथ शोध सहयोग को बढ़ावा देने के निर्णय को सराहा।

18. मंत्रियों ने आर्थिक विकास में योगदान देने वाले सशक्त, उपयोगी कार्यबल के निर्माण में कौशल के महत्व पर ज़ोर दिया। मंत्रियों ने **व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण** (VET) **की बहुराष्ट्रीय पहुँच** के लिए मॉडलों की पहचान और उनके बढ़ावे की प्राथमिकता पर सहमति प्रदान की। भारत में कौशल यूनिवर्सिटीज के साथ संभावित संस्थागत साझेदारी के अवसरों की खोज के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षकों को कौशल प्रदान करने और प्रशिक्षकों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में सहयोग के अवसरों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

19. मंत्रियों ने भारत में शैक्षणिक, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा को एकीकृत ऋण प्रणाली में ढ़ालने और शिक्षा एवं कौशल के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सक्षम गतिशीलता बनाने, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में शिक्षा अवसरों को मान्यता देने वाले **राष्ट्रीय ऋण ढांचे** (NCrF) के द्वारा पेश किए गए सहयोग के अवसरों पर भी ध्यान दिया।

20. मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य आगामी अध्ययन और सामान्य रोजगार को बढ़ावा देने वाले **पारस्परिक योग्यता मान्यता तंत्र** के तहत योग्यता मान्यता व्यवस्था को लागू करने के निरंतर प्रयासों को सराहा। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ योग्यता पद्धति पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के शिक्षा विभाग और भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मध्य वर्कशॉप पर चर्चा की और मान्यता और संस्थागत सहयोग को

और अधिक सरल बनाने के लिए भारत राष्ट्र की शिक्षा पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार की अपडेटिड प्रोफ़ाइल के आगामी प्रकाशन का उल्लेख किया।

21. मंत्रियों ने **शिक्षा टेक्नोलॉजी का लाभ** उठाने वाली साझेदारियों सहित संस्थागत साझेदारियों को सराहा। मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के शिक्षा क्षेत्रों में शिक्षा प्रस्तुति में विविधता लाने और साझेदारी के माध्यम से छात्रों को लाभ पहुंचाने की क्षमता का उल्लेख किया। मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया भारत संस्था द्वारा प्रस्तुत ऑस्ट्रेलिया-भारत InnovED फोरम और इसकी रिपोर्ट की सराहना की जिसमें हाइब्रिड एवं ऑनलाइन शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्वक और विनियमित EdTech क्षमताओं का लाभ उठाकर संस्थागत साझेदारी को समृद्ध और विस्तारित करने के अवसरों पर ध्यान दिया गया है। मंत्रियों ने विश्वव्यापी पहुँच और शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि के अभियान में टेक्नोलॉजी-समर्थित शिक्षा को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में जाना है।

22. शिक्षा और कौशल में नवीनता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों ने दोनों देशों के नियामकों के मध्य अधिक सहयोग प्रदान किये जाने का स्वागत किया। इसमें हमारे स्कूलों, कौशल और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के नियामक दृष्टिकोण के बारे में जानकारी साझा करना शामिल होगा।

23. मंत्रियों ने उच्च शिक्षा नियामकों - ऑस्ट्रेलिया की **तृतीयक शिक्षा गुणवत्ता और मानक एजेंसी** (TEQSA) और भारत के **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग** (UGC) को शिक्षा के नवीन मॉडलों की समग्रता के बारे में साझा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्वक और गुणवाचक मानकों की जानकारी को साझा करने का कार्य सौंपा। मंत्रियों ने VET नियामकों - **ऑस्ट्रेलियाई कौशल गुणवत्ता प्राधिकरण** (ASQA) और भारत की **राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद** (NCVET) के मध्य बहुराष्ट्रीय पहुँच पर चल रही साझेदारी की भी सराहना की जिसमें संबंधित नियामकों के मध्य जानकारी का समर्थन करने के लिए सहयोग और जानकारी साझा करने के अन्य अवसर शामिल हैं।

24. भावी शिक्षात्मक सफलता के सशक्त आधार के महत्व को समझते हुए, मंत्रियों ने अधिकारियों को स्कूली शिक्षा में सहयोग बढ़ाने का कार्यभार सौंपा। मंत्रियों ने पेशेवर विकास, सहयोगात्मक शोध, आदान-प्रदान, पाठ्यक्रम और शिक्षा-विज्ञान जैसे संभावित क्षेत्रों का उल्लेख किया।

25. मंत्रियों ने प्रदाताओं और उद्योग के मध्य साझेदारी के महत्व पर बात की और कार्यबल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोर्स, पाठ्यक्रमों और डिलीवरी के ढंगों में नवीनीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। मंत्रियों ने **आस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा सहयोग कार्य समूह** द्वारा किए गए कार्य की सराहना की जिन्होंने आस्ट्रेलिया और भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य अधिक संस्थागत साझेदारी और शोध साझेदारी को बढ़ाने के लिए इस सहयोग का लाभ उठाने के अवसर प्रदान किये। इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रियों ने कार्य समूह को संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहा।

26. दोनों देशों में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका और खेलों में द्विपक्षीय सहयोग को मिलने वाली प्राथमिकता को देखते हुए, मंत्रियों ने यह कहा कि श्रेष्ठता के लिए कौशल विकसित करने, नेतृत्व और नवीनीकरण को बढ़ावा देने, खेलों में संगठन, प्रशासन और अभिशासन क्षमताओं को विकसित करने और

समावेशिता को बढ़ावा देने में **खेल शिक्षा और खेल शोध** महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मंत्रियों ने खेल शिक्षा और खेल शोध में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की और संस्थानों को खेलों में कौशल, क्षमता और शोध श्रेष्ठता के निर्माण में साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया।

शोध कार्यबल के सशक्तिकरण के लिए सहयोग करना

27. मंत्रियों ने **ऑस्ट्रेलिया भारत संस्था** के रणनीतिक योगदान की सराहना की, जिन्होंने परियोजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य शोध पहलों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा, कौशल और अनुसंधान संबंधों में योगदान प्रदान किया, इसमें ऑस्ट्रेलिया-भारत महिला शोधकर्ता आदान-प्रदान कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के STEM क्षेत्रों के शोधकर्ताओं को शोध सहयोग के लिए नेटवर्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

28. मंत्रियों ने दोनों देशों के मध्य बहुविषयक और सहयोगात्मक शोध के पारस्परिक लाभ पर चर्चा की। मंत्रियों ने **शोध के व्यावसायीकरण** और शोध को उद्योग में व्यावहारिक रूप से लागू करने की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों के मध्य अग्रिम साझेदारी की सराहना की, जिसमें स्टार्ट-अप के लिए योग्य वातावरण बनाना और उद्योग के साथ प्रत्यक्ष साझेदारी करना शामिल है। इससे दोनों देशों के संबंधित क्षमतापूर्ण क्षेत्रों में तालमेल स्थापित करते हुए लाभ मिलेगा, इसपर ध्यान देते हुए **ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्था** की अगस्त 2024 की रिपोर्ट 'क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर: दीर्घकालिक शोध निवेश के लाभ' में इस बात को उजागर किया गया है कि भारत 64 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीस में से 45 में शीर्ष 5 देशों में शामिल है।

29. मंत्रियों ने द्विपक्षीय शिक्षा और शोध संबंधों को सशक्त करने में लोगों के बढ़ते संपर्कों के योगदान पर चर्चा की, इसमें विशेष रूप से ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटीज में प्राथमिक एजेंडा और शोध का नेतृत्व करने वाले भारतीय मूल के शिक्षाविदों द्वारा संचालित सहयोग शामिल है। मंत्रियों ने इस बात पर सहमति दी कि आस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के **शिक्षाविदों का फोरम** विभिन्न संस्थानों और विषयों में शिक्षाविदों को एक दूसरे से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य शिक्षा और शोध में संबंध स्थापित होंगे और ऑस्ट्रेलिया-भारत के संबंध अधिक सशक्त बनेंगे। मंत्रियों ने एक साथ मिलकर काम करने के महत्व पर भी चर्चा की ताकि शोध संबंधों को प्रवासी समुदाय और व्यक्तिगत संबंधों से आगे बढ़ाया जा सके।

30. मंत्रियों ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित संयुक्त ऑस्ट्रेलिया-भारत शोध के लिए फंडिंग योजनाओं की व्यापकता की सराहना की। मंत्रियों ने राष्ट्रीय प्राथमिकता के क्षेत्रों में शोधकर्ताओं की साझेदारी से होने वाले पारस्परिक लाभों को माना। दोनों मंत्रियों ने संयुक्त शोध कार्यक्रमों के लिए भारत की **शैक्षणिक और शोध सहयोग संवर्धन योजना** (SPARC) के तहत पहचाने गए बारह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सराहना की: i) उच्च श्रेणी पदार्थ; दुर्लभ-पृथ्वी एवं महत्वपूर्ण खनिज; ii) ऊर्जा, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन; iii) कृषि और खाद्य टेक्नोलॉजीस; iv) सेमीकंडक्टर; v) उच्च श्रेणी कंप्यूटिंग (सुपरकंप्यूटिंग, AI,, क्वांटम कंप्यूटिंग); vi) स्वास्थ्य सेवा और MedTech; vii) अंतरिक्ष और रक्षा; viii) अगली पीढ़ी के

लिए संचार प्रणाली; ix) आपदा प्रबंधन और सशक्त बुनियादी ढांचा; x) ब्लू इकोनॉमी; xi) स्मार्ट सिटीज़ और गतिशीलता; और xii) विनिर्माण और उद्योग 4.0।

31. मंत्रियों ने बताया कि SPARC के तीन चरणों के दौरान भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से कुल 119 प्रस्ताव पेश किए गए। मंत्रियों ने शोध क्षमताओं के तालमेल के बारे में बताया और संस्थानों को पारस्परिक प्राथमिकता वाले शोध क्षेत्रों में श्रेष्ठतम केन्द्रों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया।

32. मंत्रियों ने आगामी ऑस्ट्रेलिया-भारत संस्था की रिपोर्ट पर चर्चा की, जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य सहयोगात्मक शोध साझेदारी के स्तर और क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों** की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक उपलब्धि में योगदान देती है।

समापन करते हुए

33. मंत्रियों ने भारत की **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं और शिक्षा संस्थानों को जोड़ने और सहभागिता को बढ़ाने पर ज़ोर दिया और दोनों देशों को शिक्षा, कौशल और शोध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता देने के अग्रिम अवसरों पर विचार किया।

34. मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की अगली मीटिंग को 2025 में भारत में आयोजित किए जाने पर सहमति प्रदान की। इसके साथ ही, मंत्रियों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि अगली मीटिंग में **स्कूलों, कौशल और उच्च शिक्षा** पर त्रिपक्षीय ध्यान केंद्रित किया जाएगा।